राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI.No. UPHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | 9511151254 | epaper.swatantraprabhat.com | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार ,18 अप्रैल 2025
वर्ष 14, अंक 09, पृष्ट 04,मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाजियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

सीतापुर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला- जब पीड़िता ही बन गई निशाना, प्रशासन मौन!....03

पीडब्ल्यूडी- सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता और कोई समय सीमा नहीं 04

सहारा समूह की 707 एकड़ जमीन ईडी ने की कुर्क

सहारा समूह की एम्बी वैली सिटी के पास 707 एकड़ जमीन ईडी ने कुर्क की, 1460 करोड़ रुपये है कीमत।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लोनावाला के एंबी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत 1460 करोड़ रुपये की है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने सहारा समूह के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र के लोनावाला में 707 एकड़ भूमि में फैली 'एंबी वैली सिटी' को कुर्क कर लिया है। जांच एज?ंसी ने एक बयान में कहा कि यह भूमि सहारा समूह की संस्थाओं से प्राप्त धनराशि से 'बेनामी' खरीदी गई थी। एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गयी जमीन की बाजार में अनुमानित कीमत 1460 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की है। ईडी की जांच में सामने आया है कि यह ज़मीन बेनामी नामों पर खरीदी गई थी और इसके लिए जो पैसे इस्तेमाल किए गए,जो सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों से गबन करके निकाले गए थे।

ईडी ने इस मामले की जांच तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दर्ज की गई थीं। अब तक 500 से ज़्यादा एफआईआर सहारा समूह और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 300 से अधिक मामले पीएमएलए के तहत दर्ज अपराधों से जुड़े हैं।

जांच में खुलासा हुआ है कि सहारा समूह ने हजारों निवेशकों को गुमराह कर एक बड़ी पोन्ज़ी स्कीम चलाई। इन स्कीम्स के ज़रिए निवेशकों से भारी रकम जमा की गई और वादा किया गया था ऊंचे रिटर्न्स का, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया। बल्कि उन्हें जबरन दोबारा निवेश करने के लिए मजबूर किया गया।

ईडी का कहना है कि सहारा समूह ने जमाकर्ताओं की रकम को निजी खर्चों, बेनामी संपत्तियों और आलीशान जीवनशैली में खर्च किया। यह भी सामने आया है कि कई संपत्तियां नकद में बेची गईं और उन पैसों का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। अब तक की कार्रवाई में 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की जा चुकी है और कई एजेंट्स, कर्मचारियों और निवेशकों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की नजर अब सहारा समूह की अन्य संपत्तियों पर भी है जो देशभर में फैली हुई हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जड़ें और भी गहरी हैं और आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं। पुणे जिले में सह्याद्रि पर्वतीय क्षेत्र में बसे इस आवासीय शहर को इसके निर्माताओं ने एक समय ''भारत का पहला नियोजित पहाड़ी शहर'' करार दिया था, जिसमें लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली का अनुभव देने के लिए बड़े गोल्फ कोर्स, झीलें, विला, लकड़ी के बने छोटे घर या झोपडियां हैं।'एंबी वैली सिटी' मुंबई से लगभग 110 किमी और पुणे से लगभग 90 किमी दूर स्थित है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसके कोलकाता कार्यालय द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 'एंबी वैली सिटी' को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है।इसमें कहा गया कि यह भूमि सहारा समूह की कंपनियों से प्राप्त धनराशि से ''बेनामी'' नामों से खरीदी गई थी।ईडी ने कहा कि सहारा इंडिया और उसकी समूह की कंपनियों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के तहत लोनावाला (पुणे जिला) स्थित 'एंबी वैली सिटी' और उसके आसपास की कुल 707 एकड़ जमीन को कुर्क कर लिया गया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1460 करोड़ रुपये है।

ईडी ने विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में दर्ज 500 से अधिक प्राथमिकियों के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा 'हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों के अलावा, सहारा समूह की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक शिकायतों का विश्लेषण किया।ईडी ने कहा कि इनमें से 300 से अधिक प्राथमिकी पीएमएलए के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थीं...**शेष पेज 12 पर**

इफको घियानगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मनाया गया 134 वीं जयंती समारोह

इफको घियानगर फूलपुर के सामुदायिक केन्द्र में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134 वीं जयंती समारोह मनाया गया।

स्वतंत्र प्रभात

´ » U `—

समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं डॉ. दीनानाथ प्रोफेसर सी.एम.पी. डिग्री कालेज रहे। मुख्य अतिथि डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर, एकता पर तथा जीवन में संघर्ष पर बल दिया उनका मूल मंत्र रहा शिक्षित बनो, संगठित हो तथा संघर्ष करो। डॉ. दीनानाथ एवं अन्य वक्तागण एस.के.सिंह,शम्शुदोहा, शरद अग्निहोत्री, रिंकु भारती, जयंती हुड्डा,कालींदर, मकदूम फूलपुरी ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जीवन विषय पर बच्चों के लिए निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

अम्बेडकर जयंती के अवसर पर इफको टीम तथा न्यूजेन सिक्योरिटी टीम के बीच वॉलीबाल मैच खेला गया जिसमें इफको टीम विजयी रही। इस दौरान महाप्रबंधक संजय भंडारी, संयुक्त महाप्रबंधक क्रमशः एस.के.सिंह,आर.पी.यादव, विभागाध्यक्ष मानव संसाधन शम्भू शेखर, इफको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी व महामंत्री स्वयम् प्रकाश, इफको इम्पलाइज संघ के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय व महामंत्री विजय कुमार यादव,इफको एस.सी./एस.टी. वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजबली राम एवं महामंत्री हरिशंकर भारती मौजूद रहे।

संक्षिप्त ख़बरें

व्यापारी के घर चोरी, 10 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR

स्वतंत्र प्रभात

कुमारगंज -अयोध्या

कुमारगंज थाना क्षेत्र के तेंधा बाजार स्थित बर्तन व्यापारी हरिराम अग्रहरि के घर बीते 3-4 अप्रैल की रात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया लगभग एक लाख रुपये नकद और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। चोर पड़ोसी के खाली मकान की छत के रास्ते घर में घुसे और बक्से का ताला तोड़कर सामान चुरा लिया।

चोरी गए सामान में दो सोने की चैन, पांच जोड़ी पायल, पांच अंगूठियां, एक जोड़ी झुमका, एक जोड़ी झाला और पांच सेट बिछिया शामिल हैं। सुबह 5 बजे परिवार को चोरी का पता चला, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया, लेकिन 10 दिन बाद भी चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई।

पीड़ित के बेटे अवधेश ने बताया कि वह रोज थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस हर बार जांच का हवाला देकर टालमटोल करती है। थाने में कहा जाता है कि जांच जारी है। परिवार पुलिस की सुस्ती से परेशान है और उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग किया है।

बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले जस्टिस बीआर गवई होंगे अगले चीफ जस्टिस

14 मई को संभालेंगे कार्यभार।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।

यूपी में बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई देश अगले चीफ जस्टिस होंगे. वे मौजूदा सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे और 14 मई 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे. जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा. सबसे खास बात, एससी समुदाय से आने वाले वे सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई होंगे. जस्टिस गवई को सोशल जस्टिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाना जाता है.

जस्टिस बीआर गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था. उनके पिता आरएस गवई एक प्रसिद्ध राजनेता थे, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) से सांसद और बाद में राज्यपाल रहे. उनके भाई राजेंद्र गवई भी एक राजनेता हैं. जस्टिस गवई ने अपनी कानून की पढ़ाई नागपुर विश्वविद्यालय से पूरी की और 1985 में वकालत शुरू की. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत से की. 2000 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाया गया. 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया.

जस्टिस गवई के कुछ फैसले

बुलडोजर कार्रवाई पर रोक-जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यूपी में बुल?डोजर एक?शन पर रोक लगाने वाला फैसला सुनाया था. साप कहा था कि किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति को सिर्फ इस आधार पर बुलडोजर से ध्वस्त करना असंवैधानिक है. कार्यपालिका जज नहीं बन सकती और संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती.

स्टैंप एक्ट पर बड़ा फैसला-

जस्टिस गवई उस सात-जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि स्टैंप एक्ट के तहत अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट स्वीकार्य नहीं हैं. यानी अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है तो उस पर किया गया कोई भी समझौता अवैध माना जाएगा.

प्रयागराज में युवक की हत्या कर कब्रिस्तान में फेंका शव, मचा हड़कंप!

स्वतंत्र प्रभात

´ » U `—

नैनी कोतवाली अंतर्गत अरैल स्थित करबला कब्रिस्तान में बुधवार भोर में एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर उसके परिजन वहां पहुंचे और गांव के ही एक दबंग परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी पर पहुंची नैनी पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा।

मिली जानकारी के अनुसार अरैल मुरादपुर निवासी मोसिम खान (28) पुत्र निसार खान पूरा फ़तेह मोहम्मद चौराहे पर होटल चलता था। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को किसी बात को लेकर अरैल के ही एक दबंग परिवार से उसकी बातचीत हो गई थी। लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। मंगलवार शाम को वह किसी शादी आयोजन में खाना बनाने के लिए गया था। लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। सुबह सूचना मिली कि कब्रिस्तान में किसी युवक का शव पड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो तो उसकी पहचान मोसिम के रूप में हुई।

जानकारी पर परिवार वाले मौके पर पहुंचे और दबंग परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। नैनी पुलिस ने बताया कि मंगलवार को मृतक का गांव की ही एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई: पुलिस इंस्पेक्टर ने जज को ही बना दिया 'चोर', वारंट पर लिखा नाम, अब हुए सस्पेंड।

वारंट रिपोर्ट तैयार करते समय एसआई लाल ने गलती से अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) नगमा

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस अधिकारी ने जज को ही चोरी के मामले में आरोपी बना दिया। इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक (SI) को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए है। एसआई ने उसने गैर-जमानती वारंट पर रिटर्न दाखिल करते समय गलती से आरोपी के बजाय जज का नाम दर्ज कर दिया था।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौरभ ने कार्रवाई करते हुए थाना उत्तर में तैनात उपनिरीक्षक बनवारी लाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। विभागीय जांच के लिए क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार चौरसिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह घटना पिछले सप्ताह फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर में हुई थी। जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। एसएसपी (सिटी) रविशंकर प्रसाद ने पीटीआई को बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र निवासी राजकुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। वारंट रिपोर्ट तैयार करते समय एसआई लाल ने गलती से अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) नगमा खान का नाम आरोपी के रूप में दर्ज कर दिया जबकि राजकुमार आरोपी था जिसके खिलाफ जज ने शुरू में गैर-जमानती वारंट जारी किया था। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वारंट के एग्जीक्यूशन के दौरान आरोपी मौके पर नहीं पाया गया। वहीं, असली आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पू की तलाश करने के बजाय, पुलिस अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान की तलाश में लग गए जिन्होंने कानूनी नोटिस जारी किया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एसआई को पुलिस लाइन भेजने का आदेश दिया है और इस गंभीर गलती का कारण जानने के लिए घटना की जांच के निर्देश दिए हैं।

23 मार्च को सुनवाई के दौरान जब फाइल रिव्यू के लिए पेश की गई तो कोर्ट को इस गलती के बारे में पता चला। बार एंड बेंच के हवाले से मजिस्ट्रेट खान ने कहा, यह बहुत ही अजीब बात है कि संबंधित पुलिस स्टेशन के सेवारत अधिकारी को इस बात की बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस कोर्ट ने क्या भेजा है, इसे किसने और किसके खिलाफ भेजा है।

अदालत ने कहा,ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे ठीक से पढ़ा भी नहीं है। उनकी ओर से इस तरह की गंभीर गलती एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनके कामकाज के खराब तरीके को दर्शाती है क्योंकि उन्हें उनके कर्तव्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर की लापरवाही पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की लापरवाही से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है।

अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा, कार्रवाई की प्रक्रिया में शामिल पुलिस अधिकारी को उच्चतम स्तर की सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इन प्रक्रियाओं के गंभीर परिणाम होते हैं। अगर ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों को इस तरह से अंधाधुंध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी जाती है तो वे बेकाबू हो जाएंगे और अपनी मर्जी से किसी की भी स्वतंत्रता के बहुमूल्य मौलिक अधिकारों को कुचल देंगे। इसे कर्तव्य की घोर उपेक्षा बताते हुए अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच शुरू करने और इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

किसान भाई नैनो का उपयोग करे समस्या इफको हल करेगी- संजय कुदेशिया।

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

इफको फूलपुर इकाई के निकट स्थानीय गांव पूरे जाफरपुर , बाबूगंज में फूलपुर इकाई की टीम ने किसान चौपाल लगाया जिसमें किसानों को धान की फसल पर नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के प्रयोग विधि के बारे में बताया। टीम ने छिड़काव की विधि, इसकी मात्रा तथा इसके लाभ के बारे में बताया। वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (इकाई प्रमुख) संजय कुदेशिया ने किसानों से वार्ता की तथा उत्पाद के बारे में उनके मन में बैठीं भ्रान्तियों को दूर किया । उन्होनें कहा कि आप सभी किसान इसका प्रयोग करें और यदि कोई समस्या हो तो हमारी टीम से सम्पर्क करें, हम तुरंत मदद मुहैया करवायेंगे। नैनो उर्वरक के बारे में जागरूकता अति आवश्यक है। चौपाल में किसानों ने नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के प्रति उत्साह दिखाया। इस दौरान कोर्डेट प्रचार्य डॉ हरिशचन्द्र, जनसम्पर्क अधिकारी स्वयम् प्रकाश, प्रबंधक प्रशिक्षण अनुराग तिवारी, इफको इम्पलाइज संघ के महामंत्री विजय कुमार यादव, गोरख सिंह सेंगर ,राजेश सिंह, दिनेश कुमार सिंह ,ग्राम प्रधान प्रतिनिधी भास्कर सिंह पटेल मौजूद रहे।

नेटवर्क मार्केटिंग सुनहरे सपनों की छाया में पनपता सामाजिक व्यामोह

समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तब झूठे सपनों के व्यापारी सबसे अधिक फलते-फूलते हैं। जब कोई व्यवस्था बेरोजगारी से त्रस्त होती है, जब शिक्षा व्यवस्था नौकरियों की गारंटी नहीं देती, जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा से भ्रमित होता है, तब नेटवर्क मार्केटिंग जैसी अवधारणाएँ जन्म लेती हैं – और फलती-फूलती हैं। ये अवधारणाएँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के नाम पर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती हैं, जो देखने में जितनी आकर्षक है, भीतर से उतनी ही खोखली। नेटवर्क मार्केटिंग, एक प्रणाली जो दिखती है तो बिज़नेस मॉडल की तरह, लेकिन उसके भीतर छिपा है एक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक खेल। एक ऐसा खेल जिसमें कुछ लोग तो अमीर बनते हैं, लेकिन बहुसंख्यक केवल ख्वाबों का मलबा समेटते रह जाते हैं। इस प्रणाली की सबसे बड़ी शक्ति उसका भाषण है वह भाषा जो युवा आत्मा को छूती है, जिसमें प्रेरणा का उबाल होता है, जिसमें वक्ताओं की आंखों में चमक होती है और शब्दों में विश्वास। तुम भी कर सकते हो, बस दो साल की मेहनत, फिर जीवनभर की छुट्टी, नौकरी मांगो मत, नौकरी दो? जैसे वाक्य इतने दोहराए जाते हैं कि वे सच लगने लगते हैं। परंतु क्या वाकई यह सच होता है? इस सवाल का उत्तर हज़ारों ज़िंदगियाँ देती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ती हैं, सपनों को जीती हैं, और फिर चुपचाप टूटकर वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाती हैं कुछ कर्ज़ लेकर, कुछ रिश्ते तोड़कर, और कुछ अपनी आत्मा में ठहर गई ग्लानि के साथ। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला धोखा यही होता है कि यह व्यक्ति को बताता है कि यह व्यापार है, जबकि वास्तव में यह एक रिक्रूटमेंट चेन होती है एक श्रृंखला जिसमें असली उत्पाद उत्पाद नहीं, बल्कि नए सदस्य होते हैं। ऊपर बैठे लोग लीडर बन जाते हैं, जो सफलता की कहानियाँ मंच पर सुनाते हैं, लेकिन ये कहानियाँ गिनी-चुनी होती हैं हजारों उन चेहरों के पीछे छुपी, जो कभी मंच तक पहुँचे ही नहीं। व्यक्ति जब इस सिस्टम से जुड़ता है, तो सबसे पहले उसे सिखाया जाता है कि बिज़नेस अपने जानने वालों से शुरू होता है। यही वह क्षण होता है जब नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं रहती, बल्कि यह सामाजिक संबंधों का सौदा बन जाती है। रिश्ते, जो वर्षों से भावनाओं की नींव पर टिके थे, अचानक संभावित 'बिजनेस पार्टनर' बन जाते हैं। दोस्ती अब बिक्री का अवसर बन जाती है, और भाईचारा एक संभावित डाउनलाइन। यह संक्रमण केवल सामाजिक नहीं, मानसिक भी होता है क्योंकि व्यक्ति हर संवाद को अब आर्थिक संभावना के चश्मे से देखने लगता है। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से मेहनत करता है, लोगों को जोड़ता है, उत्पाद बेचता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होता है, लेकिन फिर भी उसकी आय नहीं बढ़ती। तब उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि आपने पूरी मेहनत नहीं की। यह मानसिक जाल उस व्यक्ति को आत्मग्लानि में धकेल देता है। यह प्रणाली व्यक्ति को नाकामी का ज़िम्मेदार खुद ही ठहरा देती है और यही वह जगह है जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक शोषण बन जाती है। वित्तीय नुकसान की बात करें तो यह बड़ा नुकसान, छोटी शुरुआत जैसा होता है। लोग इस सोच के साथ जुड़ते हैं कि केवल तीन-चार हज़ार से शुरुआत है, लेकिन धीरे-धीरे यह निवेश दसियों हज़ार तक पहुँच जाता है उत्पाद खरीदने, यात्रा करने, ट्रेनिंग अटेंड करने और इवेंट्स में शामिल

होने के नाम पर। और अंत में जब लाभ न मिले, तो व्यक्ति मौन होकर इस सिस्टम से बाहर निकल जाता है लेकिन तब तक वह न केवल पैसे गंवा चुका होता है, बल्कि वह अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा का एक बड़ा हिस्सा भी खो चुका होता है। सवाल यहाँ यह नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरा विचार है सवाल यह है कि इसकी क्रियान्विति कैसे हो रही है। व्यापार में लाभ-हानि सामान्य बात है, लेकिन जब व्यापार का मॉडल ही इस तरह बना हो कि अधिकतर लोग हमेशा घाटे में रहें, और केवल ऊपरी पायदान पर बैठे लोग ही समृद्ध हों तब वह व्यापार नहीं, पिरामिड स्कीम बन जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम के बेहद करीब खड़ी है। इतिहास गवाह है कि जहाँ भी लोगों को सपनों की बिक्री हुई है, वहाँ बहुत बड़ी जनहानियाँ हुई हैं चाहे वह आर्थिक घोटाले हों, धार्मिक विश्वास के नाम पर चलने वाले संगठन, या फिर मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसे कॉरपोरेट जाल। आज जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, और लोगों को अब ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्किल्स, और आत्मनिर्भर बनने के वास्तविक विकल्प मिल रहे हैं, तब नेटवर्क मार्केटिंग का यह पुराना, भावनात्मक और बार-बार दोहराया गया मॉडल अब पुनः मूल्यांकन की माँग करता है। आज आवश्यकता है कि सरकारें इस पूरे तंत्र पर कठोर नीति बनाएँ। केवल उत्पाद दिखा देने से कोई मॉडल वैध नहीं हो जाता। यह देखना अनिवार्य है कि उस कंपनी की आय किससे आ रही है उत्पाद बिक्री से, या सदस्यता शुल्क और रिक्रूटमेंट से। शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि वे वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य बनाएं ताकि युवा वर्ग जल्द अमीर बनने के भ्रम से खुद को बचा सके। और सबसे बड़ी ज़रूरत है सामाजिक संवाद की ताकि वे हज़ारों लोग जो इस सिस्टम से टूटकर बाहर आए हैं, अपनी कहानी कह सकें। क्योंकि जब तक वे कहेंगे नहीं, यह व्यापार फलता रहेगा चुप्पियों की खाद पर।नेटवर्क मार्केटिंग कोई साधारण मामला नहीं है। यह आधुनिक समाज की उस बेचैनी का लक्षण है, जो तेजी से सफल होने की चाह में, शॉर्टकट के भ्रम में, और भरोसे की तलाश में हर उस दरवाज़े को खटखटाने लगता है, जो थोड़ा भी चमकता है। लेकिन हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। और हर नेटवर्क एक 'नेट' भी हो सकता है जाल।

संपादकीय

दर्द- न धर्म देखे, न जात, बस दिल में घुस जाए बात-बात

[महंगाई में एक चीज जिसका प्रोडक्शन कभी नहीं रुका - दर्द]

इस महंगाई के दौर में, जहां एक चुटकी केसर खरीदने से पहले जेब टटोलनी पड़ती है, एक चीज ऐसी है जो अब भी मुफ्त बरसती है - दर्द। बिना टैक्स, बिना जीएसटी, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। ये ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जो दिल की चौखट पर दस्तक तक नहीं देता, सीधे अंदर घुसता है और किराएदार बनकर टिक जाता है। इसे बांटने के लिए न लाइसेंस चाहिए, न इसे लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन और न सरकार की मंजूरी। बस एक ठेस, एक ताना, एक नजर - और दर्द हाजिर, बिल्कुल मुफ्त, सीधे आपके दिल के ठिकाने पर। सब कुछ महंगा हो गया है - दाल-चावल, पेट्रोल, रिश्ते, वफादारी, और यहाँ तक कि मुस्कान भी अब क्रेडिट कार्ड पर मिलती है। लेकिन दर्द? ये तो ऐसा उदार सौदागर है जो मुफ्त में गले लगाता है और जाने का नाम नहीं लेता। ये चाय की आखिरी चुस्की की तरह चिपकता है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। दर्द का बाजार कभी मंदा नहीं पड़ता - न स्टॉक क्रैश, न रिसेशन, बस फ्री डिलीवरी, 24/7।

दर्द का डिलीवरी सिस्टम तो ऐसा है कि स्विगी-जोमैटो सब इसके सामने फीके। दोस्त का "ब्रो, तू अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ?" वाला तीर, रिश्तेदार का ÷अब तो शादी कर ले" ताना, या मोहल्ले की गुप्ता आंटी का अपने बेटे की विदेशी नौकरी का वायरल रील - हर गली से दर्द की मुफ्त डिलीवरी, वो भी '30 मिनट या फ्री' गारंटी के साथ। आंटी चुप रहें तो दर्द, क्योंकि उनकी खामोशी आपके फ्लॉप स्टार्टअप पर साइलेंट मिस्ड कॉल है। और बोलें तो दर्द, क्योंकि उनका "हमारा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में ठाठ करता ह" आपकी जिंदगी को 2-स्टार रेटिंग वाली वेब सीरीज बना देता है। ऊपर से समाज का फ्री का फंडा - "थोड़ा जॉब ढूंढो, देखो शर्मा जी का बेटा CEO बन गया!" बस, दर्द का पैकेज कन्फर्म, सीधा दिल में ड्रॉप।

ट्रेन का टिकट 700 का, मूवी का 400 का, लेकिन ब्रेकअप का दर्द? वो तो फ्लैश डिलीवरी में घर पहुंचता है, वो भी बिना शिपिंग चार्ज। प्रेमी का 'सीन' बिना जवाब? दिल में भूकंप। जवाब में "व्यस्त हूँ"? सुनामी। कोई डाउन पेमेंट नहीं, बस इमोशनल कर्ज और ब्याज में आंसुओं की किश्तें। और अगर प्रेमी ने ÷हम सिर्फ दोस्त हैं÷ कह दिया, तो समझो दिल का पूरा ढांचा ही ढह गया। सरकारी दफ्तरों में दर्द का मेला सजा है। लाइन में खड़े-खड़े कमर टूटे, वो शारीरिक दर्द। फाइल टेबल से टेबल घूमे और काम न हो, वो मानसिक दर्द। अफसर की बनावटी मुस्कान हो या चपरासी की घुड़की, दोनों मुफ्त में दिल तोड़ने का ठेका लिए घूमते हैं। आपकी फाइल ÷कल आना÷ के चक्रव्यूह में फंसती है, और समाधान सिर्फ आपके दिल में घूमता रहता है - वो भी मुफ्त का दर्द बनकर।

सोशल मीडिया तो दर्द का डिजिटल सुपरमार्केट है। किसी की मालदीव्स की तस्वीर देखी, और अपनी जिंदगी की साइकिल की हवा निकल गई। कोई नई एसयूवी फ्लॉन्ट करे, तो लगता है आपकी पुरानी स्कूटी आप पर ठहाके लगा रही है। इंस्टाग्राम की स्टोरी आपकी नींद चुराती है, और कोई फिल्टर इस दर्द को छुपा नहीं पाता। किसी ने "लिविंग माइ बेस्ट लाइफ" कैप्शन डाला, और आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर अपनी "वर्स्ट लाइफ" का हिसाब करने लगते हैं। ये दर्द मुफ्त है, लेकिन इसकी कीमत आपकी शांति चुकाती है। फिल्मों में भी यही हाल। हीरोइन की विदाई, मां का रोना, बैकग्राउंड में वायलिन। टिकट का पैसा तो वसूल, लेकिन आंसुओं की कीमत मुफ्त। पॉपकॉर्न खत्म होता है, दर्द नहीं।

शादी वो तो दर्द की लाइफटाइम फ्री सब्सक्रिप्शन है। पति का "क्या हुआ" और पत्नी का "कुछ नहीं" - ये वो डायलॉग हैं जो दर्द की स्क्रिप्ट लिखते हैं। पत्नी की खामोशी तूफान का ट्रेलर है, और पति का "बोलो न" वो बटन जो तूफान को रिलीज करता है। सास-बहू का ड्रामा? वो तो मुफ्त दर्द का बोनस पैक - ताने, तकरार, और तमाशा, सब एक ही डील में। और अगर ससुराल में "खाना नमक ज्यादा है" सुन लिया, तो समझो दर्द का मुफ्त कटोरा भर गया। दर्द का सबसे बड़ा सप्लायर है - उम्मीद। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त वक्त देगा, सरकार सस्ता राशन देगी, बॉस तारीफ करेगा, बेटा/बेटी अच्छे पढ़ेंगे, जॉब करेंगे। लेकिन जब ये सपने टूटते हैं, तो दर्द बिना नोटिस दिल में दाखिल हो जाता है। उम्मीद जितनी ऊंची, दर्द उतना गहरा। फिर भी हम हर बार उम्मीद की दुकान पर लौटते हैं, और हर बार दर्द का मुफ्त सामान लेकर घर आते हैं।

लेकिन दर्द की तारीफ करनी पड़ेगी। ये नकली नहीं, वादों की तरह झूठा नहीं, भरोसे की तरह टूटता नहीं। ये ईमानदार है- जितना देना है, उतना देता है, बिना भेदभाव। अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा, सबके लिए बराबर। ये न जात देखता है, न धर्म, न बैंक बैलेंस। ये तो बस दिल की भाषा समझता है। दर्द की मार्केटिंग भी गजब है। इसे न बिलबोर्ड चाहिए, न टीवी ऐड। ये तो मुंह-जुबानी फैलता है। एक गलत बात, एक गलतफहमी, एक टूटा वादा - और दर्द वायरल। ये फेसबुक के ट्रेंड से तेज फैलता है, और ट्विटर के हैशटैग से ज्यादा असर करता है।

इस दुनिया में जहां हर सांस की कीमत वसूल की जाती है, दर्द वो बेशकीमती रत्न है जो बिना मांगे, बिना शर्त, सीधे दिल की गहराइयों में उतर आता है। न लाइन, न सब्सिडी, न कोई टीएंडसी। बस दिल से दिल तक डायरेक्ट डिलीवरी। ये लोकतंत्र का असली नमूना है - कोई वीआईपी कोटा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं। हर वर्ग, हर उम्र, हर इंसान को बराबर हिस्सा। कहते हैं न, दुनिया में सब बिकता है। केसर, सोना, हीरा - सब की कीमत। लेकिन दर्द? वो आज भी मुफ्त है। और शायद इसलिए सबसे ज्यादा बरसता है। क्योंकि ये वो मुद्रा है जो न छपती है, न गिनी जाती है, बस महसूस होती है। तो अगली बार जब दर्द की डिलीवरी आपके दरवाजे पर आए, उसे गले लगाइए। आखिर, ये एकमात्र चीज है जो इस महंगाई में भी मुफ्त है - और पूरी ईमानदारी से आपका साथ देती है।

प्रो. आरके जैन

स्त्रियों की पुरुषों के प्रति बढ़ती क्रूर भावना- एक विमर्श

समाज में लंबे समय से स्त्रियाँ पीड़ित रही हैं - वे अत्याचार, भेदभाव और दमन की कहानियों में केंद्र में रही हैं। परंतु जैसे-जैसे समाज बदलाव की ओर बढ़ा है, स्त्रियाँ शिक्षित हुई, आत्मनिर्भर बनीं, और उन्होंने अधिकारों के प्रति जागरूकता पाई, वैसे-वैसे एक नया पहलू भी उभर कर सामने आने लगा है - कुछ स्त्रियों द्वारा पुरुषों के प्रति बढ़ती क्रूरता और भावनात्मक शोषण की प्रवृत्ति। यह विषय संवेदनशील भी है और संतुलित दृष्टिकोण की माँग करता है। हमें यह स्वीकारना होगा कि हर स्त्री पीड़िता नहीं होती और हर पुरुष दोषी नहीं होता। आज के समय में जहाँ महिला अधिकारों को लेकर सजगता बढ़ी है, वहीं झूठे आरोपों, कानूनी हथियारों के दुरुपयोग और भावनात्मक अत्याचार की घटनाएँ भी तेजी से सामने आ रही हैं।

1. कानून का दुरुपयोग

भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं - जैसे 498 (दहेज उत्पीड़न), घरेलू हिंसा अधिनियम, और यौन शोषण से संबंधित कानून। परन्तु दुर्भाग्यवश इनका कुछ स्त्रियाँ निजी स्वार्थ, बदले की भावना या झूठे आरोप लगाने के लिए दुरुपयोग भी कर रही हैं। कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जहाँ अंततः आरोप झूठे पाए जाते हैं, पर तब तक एक निर्दोष पुरुष की सामाजिक और मानसिक प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी होती है।

2. भावनात्मक और मानसिक शोषण

आजकल कई रिश्तों में यह देखा गया है कि स्त्रियाँ पुरुषों को नियंत्रित करने के लिए भावनात्मक हथियारों का प्रयोग करती हैं - कभी 'ब्लेम गेम', कभी आत्महत्या की धमकी, तो कभी सार्वजनिक अपमान का भय दिखाकर। कई बार सोशल मीडिया पर बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी पुरुष को ÷चरित्रहीन÷ घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में पुरुष मानसिक रूप से टूट जाते हैं। कुछ मामलों में तो आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है।

3. सांस्कृतिक और सामाजिक धारणा

यह धारणा गहराने लगी है कि पुरुष होना ही एक अपराध है, खासकर तब जब कोई विवाद स्त्री और पुरुष के बीच हो। यह सोच सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रही है। पुरुषों की व्यथा पर समाज खामोश है। क्या सिर्फ इसलिए कि वे पुरुष हैं?

4. परिवार और रिश्तों पर प्रभाव

रिश्तों में विश्वास टूटने लगा है। लड़के विवाह से कतराने लगे हैं, माता-पिता अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। समाज में एक अदृश्य डर फैलने लगा है - कि कहीं कोई झूठा आरोप किसी का जीवन बर्बाद न कर दे।

समाधान की दिशा- सभी कानूनों में संतुलन की आवश्यकता है - जहाँ स्त्री की सुरक्षा सुनिश्चित हो, वहीं पुरुषों के सम्मान की रक्षा भी।

पुरुष आयोग, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, और निष्पक्ष जांच एजेंसियाँ समय की आवश्यकता हैं।

मीडिया और सोशल मीडिया को उत्तरदायी आचरण अपनाना होगा - किसी भी पक्ष को दोषी ठहराने से पहले जांच और विवेक जरूरी है।

उपसंहार- समाज का ताना-बाना स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। स्त्री की गरिमा और सुरक्षा जितनी आवश्यक है, पुरुष के सम्मान और मानसिक शांति की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर कुछ स्त्रियाँ पुरुषों के प्रति क्रूर भावना पालेंगी, तो यह न केवल स्त्रीवाद की मूल भावना को ठेस पहुँचाएगा, बल्कि समाज को भी विषाक्त बना देगा। हमें ऐसे समाज की कल्पना करनी है, जहाँ नारी सम्मानित हो और पुरुष सुरक्षित। तभी हम एक सशक्त, समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ पाएँगे।

यह विषय एकतरफा दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। जहाँ आज भी करोड़ों महिलाएँ अपने हकों के लिए लड़ रही हैं, वहीं कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो नारीवाद के नाम पर पुरुषों के दमन की कहानियाँ बन चुके हैं।

1. कानूनों का दुरुपयोग- आँकड़ों में सच्चाई

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 498 A (दहेज उत्पीड़न) के अंतर्गत दर्ज मामलों में से 78त्न से अधिक केस कोर्ट में या तो खारिज हुए या झूठे साबित हुए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में कहा था- "498 A अब एक हथियार बन चुका है, जो विवाह संस्था को तोड़ने का माध्यम बन गया है।"

2. वर्तमान उदाहरण- सुष्मिता घोष बनाम आनंद मोहन तिवारी केस (2023, दिल्ली)- महिला ने पति पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से साफ हुआ कि वह खुद मारपीट करती थी। कोर्ट ने कहा - "यह महिला अधिकारों का घोर दुरुपयोग है।"

फरवरी 2024, लखनऊ- एक युवती ने अपने प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगाया, पर जांच में पता चला कि दोनों वयस्क सहमति से साथ रह रहे थे। कोर्ट ने युवती पर झूठा आरोप लगाने का जुर्माना लगाया और युवक को निर्दोष ठहराया।

3. मानसिक शोषण और सामाजिक न्याय का पक्ष- मानवाधिकार आयोग के अनुसार, हर साल भारत में औसतन 25,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या वैवाहिक विवाद, सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव से जुड़ी होती है।

"हम पुरुषों की आवाज़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते, न्याय दोनों के लिए होना चाहिए।"– पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा

4. सोशल मीडिया ट्रायल- न्याय या अन्याय?

आज सोशल मीडिया पर बिना जाँच-पड़ताल के किसी पर यौन शोषण या दुर्व्यवहार का आरोप लगाना एक चलन बन गया है। तरूद्गश्रश्व आंदोलन ने कई असली अपराधियों को उजागर किया, पर कुछ मामलों में निर्दोष लोगों को अपमान और करियर के नुकसान का सामना करना पड़ा।

उदाहरण- 2023 में बॉलीवुड लेखक वरुण ग्रोवर पर लगे आरोप बाद में झूठे निकले। पर तब तक उन्हें काम से निकाला जा चुका था।

5. समाधान की दिशा में सोच

पुरुष आयोग की स्थापना- जिस तरह महिला आयोग है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी एक स्वतंत्र निकाय की माँग तेज़ हो रही है।

झूठे केसों पर सख्त कार्रवाई- सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह कह चुका है कि झूठा मुकदमा दायर करने वाली महिला पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

संतुलित विमर्श की आवश्यकता- नारीवाद का अर्थ पुरुष विरोध नहीं, बल्कि समानता है।

समाज को ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जहाँ स्त्रियों को न्याय मिले और पुरुषों को सुरक्षा। सच्चा नारीवाद वहीं है जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों को न्याय मिले – न अधिक, न कम।

शिवम यादव "अंतापुरिया"

क्या राहुल गांधी का संकेत है राजस्थान में गहलोत-युग के पटाक्षेप का ?

पिछले सप्ताह अहमदाबाद में संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जब राहुल गांधी राजस्थान के रणथंभौर में छुट्टी मनाने आए तो यह किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वे किसी से प्रदेश में कॉंग्रेस के भविष्य के नेर्तृत्व की चर्चा भी करेंगे; लेकिन उन्होंने की,भले ही संकेतात्मक रूप से। राजनीति संकेतों और प्रतीकों में ही ज़्यादा उभर कर आती है। सियासत में दो दशक से ज्यादा सक्रिय राहुल गांधी अब इस बात को भली-भांति समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ कांग्रेस के किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि सवाईमाधोपुर के ग्रामीण क्षेत्र शेरपुर खिलचीपुर के ब्लॉक अध्यक्ष छुट्टनलाल मीणा से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेकर पूछा कि राजस्थान में कमान किसे मिलनी चाहिए? राजस्थान की राजनीति पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि यह सवाल मामूली नहीं था; इसके मायने गहरे हो सकते हैं; क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश में गहलोत-पायलट विवाद राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां रह चुका है। दरअसल राहुल गांधी का यह सवाल साबरमती के तट पर बनी पार्टी की भविष्य की रणनीति का ही एक हिस्सा है। पार्टी ने घोषणा की कि प्रदेशों में जिला समितियाँ और जिला-स्तरीय नेतृत्व निर्णय लेने और जवाबदेही का आधार बनेंगे। इसी रणनीति के तहत अधिवेशन में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उभारे गए। जूली के मंदिर में जाने के बाद 'गंगाजल से शुद्धिकरण' वाले प्रसंग को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया; इसलिए यह संयोग नहीं कि राहुल गांधी ने जिस ब्लॉक अध्यक्ष से सवाल पूछा वो दलित वर्ग से ही है और युवा भी।

देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे पुरानी पार्टी की कमान की बात अगर पहले पायलट से करें तो उनके पक्ष में अन्य बातों के अलावा महत्त्वपूर्ण मायने रखती है उनकी उम्र। उनकी और गहलोत की उम्र में करीब 26 साल का फासला है। 47 वर्षीय युवा पायलट और 73 वर्ष के अनुभवी गहलोत के बीच पांच वर्ष पहले भले ही मतभेद रहे हों और ये मतभेद पायलट के बागी होने की सीमा तक पहुंच गए हों लेकिन इससे पायलट के राजनीतिक कद में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कॉंग्रेस के केंद्रीय नेर्तृत्व के लिए वे हमेशा 'एसेट' ही रहे। राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पद छिन जाने के बावजूद पायलट ने जिस ख़ामोशी से संयम और गरिमा को बनाए रखा, यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। उससे इनके कद में बढ़ोतरी ही हुई और केंद्रीय नेर्तृत्व ने उन्हें पार्टी का महासचिव बना कर उनके महत्व को स्वीकार भी किया। जातिगत आधार पर भी पायलट जिस गुर्जर वर्ग से आते हैं, उसका राज्य की राजनीति में काफी प्रभाव है। राज्य की 30-35 सीटों पर गुर्जर जाति का प्रभाव है। गुर्जर परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ माना जाता था पर 2018 के विधानसभा चुनाव में पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में पायलट-गहलोत विवाद से गुर्जरों की नाराजग़ी कांग्रेस को काफी भारी पड़ी।

राजस्थान में 34 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 जनजाति के लिए आरक्षित हैं तो 100 से अधिक सीटों पर ओबीसी समूहों का खासा प्रभाव है। जाट, माली कुम्हार और कुमावत सहित सभी जातियां अब राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग और सचेत हो गई हैं। गुर्जर भी इन्हीं में आते हैं। इन सबमें माली समुदाय अपेक्षाकृत छोटा है। अशोक गहलोत इसी समुदाय से आते हैं। पिछली विधानसभा में पायलट के गुर्जर समुदाय से आठ विधायक थे जबकि माली समुदाय से एकमात्र विधायक गहलोत ही थे। कमान के अलावा राजस्थान में लगातार वोट संख्या को लेकर भी कांग्रेस की चिंता और चुनौतियां कम नहीं हैं। पिछले चार विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के बीच वोट का अंतर न केवल घटता गया है बल्कि 2023 के चुनाव में तो भाजपा आगे भी निकल गई।

ऐसे में कांग्रेस अगर नेर्तृत्व की कमान किसी युवा, जातिगत समीकरणों में समायोजित होने वाले लोकप्रिय नेता के हाथों में देना चाहे तो पायलट 'अ सूटेबल बॉय' हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी ठोस यथार्थ है कि इसे अशोक गहलोत के युग का पटाक्षेप मानना जायज़ नहीं होगा। सच यही है कि आज भी कांग्रेस में अनुभव, राजनीतिक कूटनीति विपक्ष के दांवपेंच को समझने में अशोक गहलोत के पासंग कोई नहीं है। उनके समवयस्क अन्य नेताओं में संगठन और सरकार चलाने का ठोस अनुभव और प्रशासनिक क्षमता उतनी नहीं है, जितनी गहलोत ने आधी सदी में अर्जित की है। गहलोत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा किया। 1974 में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर 1977 में कांग्रेस के संकटकाल में अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पहला चुनाव लड़ चुके गहलोत इस रेगिस्तानी सीमांत प्रदेश के गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक पग-पग नाप चुके हैं। यह गहलोत की नेर्तृत्व-क्षमता ही थी जिसे महसूस कर सोनिया गांधी ने 2022 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन ही लिया था लेकिन स्वयं गहलोत ने इससे किनारा कर सबको चौंका दिया था। इसके बावजूद गांधी परिवार का गहलोत में विश्वास बरकरार है। राज्य में भविष्य का नेर्तृत्व तैयार करने के लिहाज से भले हो राजस्थान की कमान पायलट को सौंप दी जाए लेकिन पार्टी गहलोत के अनुभव, पार्टी के प्रति आधी सदी की प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय पहचान के मद्देनज़र उन्हें नज़रंदाज़ नहीं कर सकती। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य, मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ती उम्र और राहुल गांधी की अनिच्छुकता के चलते संभव है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को राजस्थान से ही मिले।फिर भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो अक्टूबर 2022 में खुद अशोक गहलोत ने कही थी - राजनीति 'गुणा-भाग' का खेल है, जहां जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है।

हरीश शिवनानी

वक्फ बोर्ड क़ानून पर सुनवाई बेमतलब

अब चूंकि याचिकाएं आई हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को उनकी सुनवाई करना पड़ रही है। माननीय अदालत का करम है कि उसने तमाम याचिकाओं को एक झटके में खारिज नहीं किया ,हाँ माननीय कोर्ट ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग जरूर ठुकरा दी थी। देश को और इस क़ानून के विरोधियों को भले ही सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद हो ,लेकिन मुझे नहीं है ,क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस क़ानून को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई फैसला देगा। मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड कानून पर सुनवाई का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये कानून संसद के दोनों सदनों में लम्बी बहस के बाद बहुमत से पारित किया गया है। ये कानून भले ही संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध हो किन्तु इसमें सरकार की भावना महत्वपूर्ण है और माननीय कोर्ट इसे भली- भांति समझता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इशारों-इशारों में माननीय कोर्ट को सरकार की भावना से अवगत भी करा दिया है। किरण ने पिछले दिनों ही कहा था कि माननीय न्यायालय को वक्फ बोर्ड क़ानून पर सरकार की भावना समझना चाहिए।

वक्फ बोर्ड कानून सत्ता प्रतिष्ठान के हिन्दू एजेंडे से ही बाबस्ता है। सरकार शुरू से एक देश, एक क़ानून और एक देश ,एक चुनाव की बातें करती आ रही है। मौजूदा सरकार स्पष्ट रूप से देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आजादी के बाद बने तमाम कानूनों को जमीदोज कर अल्पसंख्यकों के कामकाज,धारणाओं, मानयताओं में मदाखलत करने की कोशिश कर रही है। सरकार को लगता है कि इस देश में सिवाय हिन्दुओं के सभी लोग चोर हैं,बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं ,इसलिए उनके खिलाफ कार्रावाई के लिए नए कानूनों की जरूरत है। कौन सा समाज किस तरह से जीवित रहेगा इसकी फ़िक्र समाज से ज्यादा अब सरकार को होने लगी है और नया वक्फ कानून इसी फ़िक्र का नतीजा है।नयेकानून किमुखालफत करने वालों को सत्ता प्रतिष्ठान और उससे जुड़े लोग पहले हिअरबन नक्सली कह चुके हैं।

मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम अधमरे चौथे स्तम्भ के लोग संसद से बड़े नहीं है। अदालतों से बड़े नहीं हैं ,लेकिन हमारी चिंताएं हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं और उन्हींके तहत हम सत्ता प्रतिष्ठान को आगाह करते रहते हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जैसा कि सरकार का है। हमें ऐसा कोई भय नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश पर अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाएगा। हमें केवल एक ही डर है कि हमने यानि देश ने आजादी के बाद जिस तरह से समरसता का, समन्वय का देश बनाया था वैसा देश अब शायद बचा नहीं है। आज हमारा देश इंद्रधनुष के रंगों वाला देश नहीं है, आज देश को एक रंग में रंगने की बेशर्म कोशिश हो रही है।

बात नए वक्फ बोर्ड क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने की है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इसीलिए है क्योंकि वो सभीको सुनता है।सरकार सबको नहीं सुनती। लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक बात सामान्य हैकि दोनों जगह बहुमत से फैसले किये जाते हैं। मेरा अंतर्मन कहता हैकि जिस तरीके से संसद में बहुमत इस नए क़ानून के पक्ष में खड़ा था उसी तरह से अदालत में भी बहुमत का फैसला आएगा तो सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केवल सरकार ही बदल सकती है। सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है ,कोर्ट ने अतीत में अनेक प्रकरणों में या तो सरकार के फैसले बदले हैं या उनकी समीक्षा कराई है। ऐसी भी अनेक नजीरें हैं जहाँ सत्ता प्रतिष्ठान से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मैंने से इंकार कर दिया और नयी व्यवस्था दे दी। मै इस तरह की नजीरों की तफ्सील में नहीं जाऊंगा समझदार को इशारा काफी है। जब जिसका बहुमत होता है वो पार्टी और उसकीसरकार अपने ढंग से माननीय न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हैं,करते आ रहे हैं।

नए वक्फ बोर्ड क़ानून को लेकर मेरी आशंकाओं के पीछे कुछ ठोस आधार है। पहले का संकेत मैंने किया ही और अब दूसरे मामले में मै सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई को उद्धृत करना चाहता हूँ। जस्टिस गवई ने डॉ. आंबेडकर की जयंती के मौके पर कहा कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम यहां संविधान की वजह से पहुंचे हैं।

जस्टिस गवई से पहले पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ देश के प्रधानमंत्री के साथ गणपति वंदना कर चुके हैं। जिस देश का कोर्ट देश के प्रधानमंत्री के प्रति शृद्धानवत हो उस देश में कोई फैसला सरकार के खिलाफ भला आ सकता है क्या देश के प्रधानमंत्री के प्रति शृद्धा रखना क़ानून कोई जुर्म नहीं है किन्तु यदि देश का सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक रूप से पंत प्रधान की वंदना करता है तो वो आपत्तिजनक है।

बहरहाल आने वाले दिनों में आप रोजाना वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखिये, सुनिए और फिर बताइये की मै गलत हूँ या सौ फीसदी सही ?मै उन लोगों में से हूँ जो इस देश की पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था पार यकीन रखते हैं। फिर चाहे वो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का हो या मुंशी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का।

राकेश अचल

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगेस्टर एक्ट के 4 इनामी बदमाश झारखंड से गिरफ्तार

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश।पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के सख्त निर्देशन में जनपद में वांछित और पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में कोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी ओबरा के पर्यवेक्षण में थाना कोन पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के एक मामले में वांछित चार इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।थाना कोन में दर्ज मु0अ0सं0-72/25, धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहे इन चारों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त फरार चल रहे चारों अभियुक्तों को धर दबोचा।गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान बृजेश पासवान पुत्र गोविन्द पासवान, डब्बू यादव उर्फ डबलू यादव पुत्र शिवनन्दन यादव, नारायण यादव पुत्र भरत यादव और लल्लन प्रसाद यादव (स्वर्गीय सुखाड़ी प्रसाद यादव) के रूप में हुई है। ये सभी पिपरा थाना खरौंधी जनपद गढ़वा, झारखंड के निवासी हैं। पुलिस टीम ने इन चारों को अमिला धाम चकरिया से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मुख्य रूप से प्रभारी निरीक्षक थाना कोन, उप निरीक्षक हवलदार पाल चौकी प्रभारी चॉचीकला थाना कोन, हेड कांस्टेबल विनोद सिंह यादव, हेड कांस्टेबल पंकज राय, हेड कांस्टेबल संजय यादव और कांस्टेबल देवेन्द्र पाल चौकी चॉचीकला थाना कोन शामिल थे। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी और कहा कि जनपद में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध करने वाले तत्वों में भय का माहौल है।

ओबरा पुलिस द्वारा फरार चल रहे 03 नफर अभियुक्तो को किया गिरफ्तार , भेजा न्यायालय

ओबरा/सोनभद्र- पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व फरार चल रहे व पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा वांछित वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पाण्डेय के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक ओबरा के कुशल नेतृत्व में बुधवार को काफी समय से फरार चल रहे वारण्टी/अभियुक्तगण मु0नं0 14523/2025 धारा 60अबकारी अधि0 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राहुल स्वीपर पुत्र नरायन निवासी सेक्टर नं0 10 शाक्तिनगर कालोनी ओबरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 30 वर्ष, मु0नं0 4401/22 धारा 60अबकारी अधि0 व मु0नं0 4876/20 धारा 60 अबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त गुड्डू स्वीपर पुत्र स्व0 सिंगार चन्द्र निवासी शान्तिनगर ओबरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष, मु0नं0 3916/24 धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त इरशाद अली उर्फ मुन्नु पुत्र स्व0 अब्दुल शकूर अली निवासी एलआईसी आफिस के पीछे कैरियर कानवेन्ट एजुकेशनल स्कूल के पास मिल्लतनगर ओबरा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र । उपरोक्त तीनो वारण्टी/अभियुक्तो के विरुद्ध मा0 न्यायालय से एनबीडब्लू के तहत गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ था । उक्त आदेश के क्रम में थाना ओबरा पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में मुख्य रूप से उ0नि0 रामलोचन , उ0नि0 राजेश दुबे, हे0का0 विजय यादव , हे0का0 संतोष पटेल शामिल रहे।

अदालतीं नोटिस

सावित्री आदि... बनाम...राजेश

मु.सं-T202104680702636

न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय उपजिलाधिकारी न्यायिक तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर में राजेश ने मु अंतर्गत धारा 24 उ. प्र. रा. सं. 2006 के अंतर्गत यह आवेदन किया है

अतः एतद्द्वारा आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ दिनांक 22-04-2025 के दिवस को पूर्वाह्न या सम्यकरूपेण अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजात है। ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय रुप से सुना और आधारित किया जाएगा।

1- सावित्री पत्नी रामबली निवासी ग्राम सरेसर परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।

सीतापुर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला- जब पीड़िता ही बन गई निशाना, प्रशासन मौन!

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर। जनपद में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले का मामला दिनोंदिन गंभीर होता जा रहा है। एक ओर जहां इस मामले में करोड़ों रुपये के लेन-देन के आरोप सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों को न्याय की जगह धमकियां, बदनामी और अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। सिधौली की सामाजिक कार्यकर्ता और आवेदिका शीला रावत की आपबीती इस पूरे भ्रष्टाचार की बानगी है, जो सिस्टम की संवेदनहीनता और मिलीभगत को उजागर करती है। शीला रावत ने बताया कि सिधौली सीडीपीओ कार्यालय में तैनात बाबू पूनम द्विवेदी ने उनसे ?3 लाख की मांग की थी। यह बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और उन्होंने इसे मीडिया व संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित किया है। उन्होंने ढ्ढत्रक्रस् पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी, परंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

यही नहीं, जांच के लिए जब खैराबाद की सीडीपीओ को नियुक्त किया गया, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग को नकारते हुए यह कह दिया कि उसमें "पैसे की बात स्पष्ट नहीं है"। शीला का कहना है कि –"हमने स्पष्ट कहा कि फोन पर कोई सीधे पैसे की बात नहीं करता, पर अंदाज़, इशारे और संवाद सब कुछ कह जाते हैं।÷ पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि सीडीपीओ और उनके साथ जुड़े कुछ लोग उन्हें तरह-तरह से डराने और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बदनाम करने की योजना रची गई और उनके विरुद्ध झूठी कहानियां फैलाने की भी साजिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में सीडीपीओ कार्यालय की भूमिका पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो जांच उन्हीं के विभाग के अधिकारियों से कराना कैसे निष्पक्ष हो सकता है? यह सीधा-सीधा हितों का टकराव है। शीला रावत कहती हैं –"अगर दोषी ही जांचकर्ता बन जाएं, तो पीड़ित को कब, कहां और कैसे न्याय मिलेगा?" उनकी मांग है कि यह मामला स्वतंत्र जांच एजेंसी (SIT, CBCID या लोकायुक्त) को सौंपा जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। शीला ने बताया कि जिले के उच्च अधिकारी इस गंभीर घोटाले पर पूरी तरह से मौन हैं। कोई भी अधिकारी उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। न तो दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई, न ही पीड़िता को संरक्षण मिला।

न्याय की उम्मीद में अब शीला रावत ने निर्णायक कदम उठाने का मन बना लिया है। उन्होंने बताया कि –"कल मैं विकास भवन में आमरण अनशन कर रहे सत्याग्रहियों का साथ दूंगी और इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करूंगी।" सीतापुर का आंगनबाड़ी भर्ती घोटाला यह बताने के लिए काफी है कि जब सिस्टम में बैठे लोग ही भ्रष्टाचार में शामिल हों, तो पीड़ित को न्याय के लिए किस हद तक संघर्ष करना पड़ता है। शीला रावत की लड़ाई न केवल उनके हक की है, बल्कि हर उस महिला की आवाज़ है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है। यदि शासन-प्रशासन अब भी नहीं चेता, तो यह मामला एक और सामाजिक विद्रोह का बीज बन सकता है।

डिबुलगंज अस्पताल में मंत्री जी का 'दानोत्सव'- सवालों के घेरे में सरकारी तंत्र

अनपरा, सोनभद्र। ओबरा विधानसभा क्षेत्र के डिबुलगंज स्थित संयुक्त चिकित्सालय में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड द्वारा आयोजित एक उद्घाटन समारोह ने क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। दरअसल, मंत्री जी ने यहां दो कूलर और दो कुर्सियों का उद्घाटन किया, जो एक स्थानीय राख ट्रांसपोर्टर द्वारा दान किए गए थे। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और राजनीतिक प्रचार के नए तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां तक उपलब्ध न हों और गर्मी से राहत के लिए कूलर भी निजी दान पर निर्भर हों, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी तंत्र इतना भी सक्षम नहीं है कि वह अपने अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सके।इस घटना ने एक और विवाद को जन्म दिया है। दान करने वाले राख ट्रांसपोर्टर पर नदी-नालों को पाटकर प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में, लोगों का मानना है कि मंत्री जी द्वारा उनके दान का उद्घाटन करना न केवल अनैतिक है, बल्कि सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगाता है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या यह %दान% सरकारी तंत्र का सहयोग है या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक प्रयास,अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि महीनों से इन्वर्टर बैटरी में पानी न होने के कारण बंद पड़ा था, और इस पानी को डालने का खर्च भी उसी राख ट्रांसपोर्टर ने उठाया। इससे अस्पताल की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं।उद्घाटन समारोह को जिस भव्यता से आयोजित किया गया, उससे लोगों को लगा कि अस्पताल के कायाकल्प के लिए कोई बड़ी योजना शुरू होने वाली है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मंत्री जी केवल कूलर और कुर्सियों का उद्घाटन करने आए हैं, तो वे निराश हो गए और तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे। लोगों का मानना है कि यह एक राजनीतिक स्टंट था, जिसका मकसद मंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ाना था।इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सरकारी तंत्र की विफलता है या फिर जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास? यह घटना सरकारी तंत्र और राजनीतिक प्रचार के बीच की धुंधली रेखा को भी उजागर करती है।

अपराधियों को किसी कीमत पर बशा नहीं जाएगा - द्विवेदी

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। रहीमाबाद थाना के नए थाना प्रभारी के रूप में आनंद द्विवेदी ने अपना पदभार ग्रहण किया।उन्होंने कार्यभार संभालते ही क्षेत्र की जनता की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। आनंद द्विवेदी ने कहा कि उनकी मुख्य जिम्मेदारी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर अंकुश लगाना होगी।प्रभारी द्विवेदी ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस हमेशा जनता के साथ है और उनकी सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।उन्होंने अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है।इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने में मदद मिलेगी। थाना प्रभारी आनंद द्विवेदी ने कहा कि उनकी पूरी टीम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करेगी, ताकि क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस करें और कानून व्यवस्था कायम रहे।

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को कानून का सामना करना होगा ˜ केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से दायर की गई चार्जशीट पर टिप्पणी की। इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं पर भी राय व्यक्त की। केशव प्रसाद मौर्य ने बंगाल में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया।

केशव प्रसाद मौर्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की है। अगर कांग्रेस देश के कानून का सम्मान करती है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने और कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून अपना काम करेगा और जो भ्रष्टाचारी है, वह नहीं बचेगा। ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और वे इस मामले में जमानत पर हैं। अगर कांग्रेस बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान और देश के कानून का सम्मान करती है, तो उसे भ्रष्टाचार के आरोपों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करना कांग्रेस की घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए संविधान और कानून एक समान है। लेकिन कांग्रेस यह सोचती है कि गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कानून काम न करे, जो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, जिसने देश को लूटा, गरीबों और किसानों को लूटा, या विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

मौर्य ने आगे कहा कि साल 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, तब नेशनल हेराल्ड मामले की जांच शुरू हुई। जांच पूरी होने में समय लगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में यह प्रक्रिया पूरी हुई। जब आरोप सही पाए गए, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत लेनी पड़ी। सारे सबूत उपलब्ध हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस इस मामले में घटिया आचरण और राजनीति कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं।

पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के बाद जो हिंसा हो रही है, इसके लिए मैं ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन सिर्फ ममता सरकार ही नहीं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वे सभी दल जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मतदान किए हैं, वे भी इसके दोषी हैं। वहां हिंदुओं और गरीबों पर हमले हो रहे हैं, दुकानें और मकान जलाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। फिर भी ये दल चुप हैं। इस तरह चुप रहने

वालों को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय और इतिहास सब कुछ उजागर करेगा। आज जो हो रहा है, उसके लिए उन्हें कल जवाब देना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी जा रही है और वहां भाजपा की सरकार आ रही है। लेकिन वर्तमान में वहां के हालात बहुत खराब हैं। ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है। वहां का हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता- सीएम योगीउत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता- सीएम योगी

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र और कार्य की प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत इनमें बदलाव किया जाना चाहिए।

बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, साथ ही, प्रत्येक जनपद में एक-एक कार्यालय स्थापित किया जाए। जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों के समुचित समाधान के लिए बोर्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक कचरा, ई-वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सेल का गठन किया जाए। इसी प्रकार, लोक शिकायत निवारण के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन हेतु, पर्यावरणीय जन-जागरूकता और प्रकाशन हेतु आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु विशेष यूनिट का गठन भी किया जाना चाहिए। इससे बोर्ड की प्रभावशीलता पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

बैठक में सीएम योगी ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण 120 दिनों में किया जा रहा है। इसे क्रमशः अभी 40, 25 और 10 दिनों में किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित करें।

उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाए। बेहतर होगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड को गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

नोएडा के डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, 150 करोड़ की जमीन मुक्त

स्वतंत्र प्रभात

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने हिंडन और यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और फार्म हाउसों के निर्माण को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डूब क्षेत्र में हो रहे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बुधवार सुबह 10 बजे ग्राम हेबतपुर में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। यह संयुक्त अभियान नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग (तहसील दादरी) और पुलिस बल की उपस्थिति में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 120 बीघा डूब क्षेत्र की भूमि को अवैध निर्माणों से मुक्त कराया गया। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

ध्वस्तीकरण अभियान में नोएडा प्राधिकरण के लगभग 250 कर्मचारी, 3 जेसीबी मशीनें और 5 डंपर तैनात किए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और भू-माफियाओं पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ने आमजन को चेतावनी दी है कि वे डूब क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र में हो रही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनी बनाने में संलिप्त अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अनधिकृत निर्माणों को न केवल ध्वस्त किया जाएगा, बल्कि इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि डूब क्षेत्र में अब अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर ओबरा क्षेत्र में 4 क्रेशर सीज, मचा हड़कंप

स्वतंत्र प्रभात

ओबरा/डाला। शासन और क्रेशर यूनियन की लगातार अपीलों के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रेशर संचालकों के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण टीम ने ओबरा, डाला-बिल्ली मारकुंडी और डाला बारी क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय न पाए जाने पर टीम ने मौके पर ही 4 क्रेशर प्लांट को सीज कर दिया, जिससे क्षेत्र के क्रेशर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण टीम ने बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में 2 और डाला क्षेत्र में 2 क्रेशर इकाइयों को सीज किया। इसके अतिरिक्त, टीम ने नियमों का पालन न करने वाले 2 अन्य क्रेशर संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

इस कार्रवाई के दौरान मौके पर खनन निरीक्षक मनोज, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्कष्टक्च) के वैज्ञानिक सुशील कुमार और बिल्ली मारकुंडी के लेखपाल अमित सिंह मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने क्रेशर प्लांटों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अपर्याप्त व्यवस्थाएं पाए जाने पर टीम ने तत्काल सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य क्रेशर संचालकों में भी दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई उन सभी क्रेशर इकाइयों के लिए एक कड़ा संदेश है जो नियमों को ताक पर रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं।गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ओबरा और आसपास के क्षेत्रों में क्रेशर प्लांटों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद जिलाधिकारी ने एक संयुक्त टीम का गठन कर निरीक्षण के आदेश दिए थे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण और नियमों का पालन सर्वोपरि है और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी क्रेशर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जताई है कि प्रशासन आगे भी इस तरह की सख्ती बनाए रखेगा।

बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग, बिजली संकट ने भी बढ़ाई परेशानी

● नगर क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है शास्त्री नगर का यह मोहल्ला

स्वतंत्र प्रभात

चित्रकूट।"शहर में रहकर भी गाँव जैसी हालत" – यह कहावत शास्त्री नगर के शोभा सिंह का पुरवा मोहल्ले पर पूरी तरह फिट बैठती है। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी के अधीन आने के बावजूद यह क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहां के लोग बीते पंद्रह दिनों से नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं देख पाए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पानी के लिए दिनभर परेशान रहते हैं, और किसी तरह दूर-दराज से पानी लाकर गुजारा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा, जिससे पूरे मोहल्ले में हाहाकार मचा है। महिलाएं और बच्चे सुबह से ही बाल्टियां और डिब्बे लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग आसपास के मोहल्लों से पानी लाने को मजबूर हैं।

इस गंभीर समस्या को देखते हुए वार्ड 21 के सभासद शंकर प्रसाद यादव ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता डी. के. सत्संगी को अवगत कराया। उनकी पहल पर जल संस्थान के जेई को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने जाकर पेयजल संकट की पुष्टि की। हालांकि निरीक्षण हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

पानी की समस्या के साथ-साथ बिजली व्यवस्था भी इस मोहल्ले की एक और बड़ी परेशानी है। क्षेत्र की कई गलियों में आज तक बिजली के खंभे नहीं लगाए गए हैं। मजबूरी में लोग बांस-बल्ली के सहारे केबल बिछाकर बिजली की सप्लाई ले रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। हादसे की आशंका हर समय बनी रहती है।

शोभा सिंह का पुरवा भले ही नगर क्षेत्र में शामिल है, लेकिन इसकी हालत किसी ग्रामीण क्षेत्र से कम नहीं है। यहां आज भी सड़कों की हालत खस्ताहाल है, नाली सफाई नहीं होती, और न ही नियमित कूड़ा उठान होता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि विद्युत विभाग और जल संस्थान की लगातार अनदेखी ने उनके जीवन को नारकीय बना दिया है। मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस इलाके में शीघ्र अति शीघ्र पेयजल और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो लोग प्रदर्शन और धरना देने को मजबूर होंगे।

भिखारी बाबा आश्रम परिसर में विराट रुद्र महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने की यज्ञ मंडप की परिक्रमा

● शिव शक्ति महिला मंडल एवं भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट ने किया आयोजन

रामगढ़ कसारी स्थित भिखारी बाबा आश्रम परिसर में चल रहा कार्यक्रम

स्वतंत्र प्रभात

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश – रामगढ़ कसारी स्थित भिखारी बाबा आश्रम परिसर में चल रहे विराट रुद्र महायज्ञ में बुधवार को दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से समूचा यज्ञ स्थल गुंजायमान रहा। प्रतिदिन चलने वाले विशाल भंडारे में श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के आयोजक/ संयोजक भिक्षुक भिखारी जंगली दास दीनबंधु रमाशंकर गिरी जी महाराज ने बताया कि भिखारी बाबा आश्रम परिसर में नौ दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विराट रूद्र महायज्ञ के दुसरे दिन बुधवार को श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से समूचा यज्ञ स्थल गुंजायमान हो गया।यज्ञाचार्य राजेश तिवारी, आचार्य योगेश तिवारी, आचार्य गिरीश पाठक के जरिए विराट रुद्र महायज्ञ के दूसरे दिन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। प्रतिदिन चलने वाले विशाल भंडारा में श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। नागालैंड से आए संत शिरोमणि कथा व्यास पंडित राजेश तिवारी के जरिए सुनाई गई कथा का भी श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। विराट रुद्र महायज्ञ के यजमान परमानंद मौर्या व उनकी धर्मपत्नी भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट की उपाध्यक्ष चिंता मौर्या के साथ ही राजकुमार गुप्ता, रीता देवी, करुणा सिंह,सीता अग्रवाल, सत्या मौर्या, कलावती चौबे,कृष्णावती, विमला देवी आदि मौजूद रही।

संक्षिप्त खबरें

एसकेपी इंग्लिश मीडियम स्कूल ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव समारोह

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पूर्व विधायक ने किया पुरस्कृत

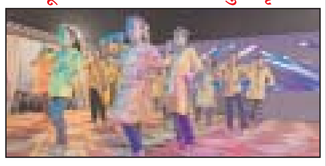

लंभुआ। सुल्तानपुर शिक्षा से ही हम अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से परिश्रम कर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उक्त बातें लंभुआ क्षेत्र में स्थित एसकेपी इंग्लिश मीडियम स्कूल चौकिया में आयोजि वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने कही। स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम की मौजूद लोगों ने सराहना की। वर्ष 2024- 25 में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व विधायक श्री द्विवेदी ने पुरस्कृत किया। उन्होंने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधक शिवा जी सिंह ने पूर्व विधायक को स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा भेंट किया। प्रधानाचार्य स्वाधीन ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मौके पर श्रीमती सविता सिंह, धीरेंद्र सिंह, गौरव सिंह, आशुतोष सिंह, साधू मिश्रा, विपिन यादव आदि मौजूद थे।

बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत

मृतक का फाइल फोटो

सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर सिंगरजोत मार्ग पर मल्हार गांव के पास मंगलवार की सुबह खड़ी डंपर में भिड़ी बाइक जिसमें बाइक सवार प्रमोद की इलाज के दौरान मौत हो गई।मंगलवार को हुई घटना में एक मासूम बच्ची सहित चार लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से सीएससी सिरसिया पर लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।जानकारी के अनुसार ग्राम नावडीह निवासी प्रमोद कुमार पुत्र चिनगुद उम्र 32 वर्ष का था जो सोमवार को अपने बहन को लाने के लिए मगराव गांव में गए हुए थे। फिर मंगलवार को वापसी सुबह के समय में डीलक्स बाइक से घर आ रहा था। मल्हवार गांव के निकट पहुंच ही था कि बेकाबू बाइक सवार अचानक डम्फर गाड़ी में पीछे से जाकर भिड़ गई। बाइक सवार प्रमोद कुमार, उनकी बहन किरन , मोहन लाल बहनोई, भांजी खुशी भी सवार थे। भांजी खुशी और प्रमोद को गंभीर चोट आई थी और उसकी बहन किरन, मोहन लाल बहनोई सहित सभी घायलों को कैली हैस्पिटल में भर्ती कराया गया वहां पर चिकित्सकों ने प्रमोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। उनके भांजी खुशी व बहन किरन, तथा बहनोई मोहन लाल तीनों को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया।

दुकानदार कालाबाजारी न करने पाए- जिलाधिकारी

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्यवृत्त को पढ़ा गया, जिसमें अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने किसान दिवस में उपस्थित किसानों की समस्याओं को सुना गया। जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने निर्देश दिया कि किसानों द्वारा की जा रही मांग को समय से पूर्ण कराये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित कराने का निर्देश दिया गया। कोई भी दुकानदार कालाबाजारी न करने पाए। सभी अधिकारी किसानों की समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण करायें।जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 ने सम्बन्धित को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों को संबधित अधिकारियों को प्रेषित करके उनकी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कराये। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को मिलना चाहिए। इस बैठक में उप कृषि निदेशक अरविन्द कुमार विश्वकर्मा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दूबे,जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं किसान व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 134 वी जयंती 14 अप्रैल को बुढार बस स्टैंड धर्म कांटा के पास बहुजन गोंडवाना गणतन्त्र पार्टी के द्वारा मनाया गया

स्वतंत्र प्रभात

शहडोल। जिसमें बाबा साहब के द्वारा संविधान को मूर्त रूप देने के संबंध में कहा गया कि उनके द्वारा ही दलित वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता बाबासाहब के द्वारा ही मिली है और आज हमें शिक्षित होने और संगठित होने की जरूरत है नहीं तो दलित वर्ग बहुत पिछड़ता जाएगा और साथ ही बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, आज जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं भविष्य को ध्यान में रखकर ही बाबा साहब ने अपने विचारों के साथ कानून को बनाया था की आने वाले समय में कभी भी दलितों के साथ अत्याचार अन्याय ना हो क्योंकि वह अपने जीवन काल में ही अपने दलित वर्ग के सामाजिक क्षेत्र में कुरीतियों को देखते हुए संविधान की रचना की थी। अंबेडकर जयंती के मुख्य अतिथि श्रवण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज दलित समाज बहुत ही पीड़ित है और केवल उनका उपयोग किया जा रहा है जबकि उनके साथ अत्याचार और अन्याय पूरे भारत में रोज कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है आज मैं अपनी माताओ बहनों से यह कहना चाहता हूं की एक रोटी कम खाकर बच्चों को अपने शिक्षित करें और हमेशा संगठित रहे जिससे हम लोगों की मजबूती रहे, वह आने वाले समय में हमारे बच्चे देश का भविष्य बनकर समाज के लिए कार्य करें।

इसी उद्बोधन की कड़ी में कार्यक्रम की अध्यक्ष एवं वरिष्ठ दलित नेता अमृतलाल चौधरी ने भी अपनी जीवन की गाथा के संबंध में कहा कि हमने भी इस संबंध में काफी यात्राएं की और हम यूपी से चलकर आज शहडोल जिले में एक शासकीय नौकरी को छोड़कर समाज की सेवा में लगा हुआ हूं और मेरा उद्देश्य अपने समाज को उत्थान के लिए आखिरी सांस तक लगा रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी परेशानी हो, मुसीबत झेलना पड़े मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मंचासीन अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखें जिसमें उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया, वह हमारे मसीहा है और हमेशा रहेंगे। हमें शिक्षित और संगठित होकर समाज के लिए कार्य करना है यही बाबा साहब का भी उद्देश्य था। इस अवसर पर बहुजन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने भी बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारकर भविष्य की गाथा हमें लिखना है और बाबा साहब का सपना था जिसे हम लोग पूरा करेंगे। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बहुजन गोंडवाना गण पार्टी के बादल चौधरी सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आमजन मौजूद थे। वही बहुजन गोंडवाना पार्टी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती एवं शोभा यात्रा निकाली गई जो मुख अतिथि बहुजन गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुध नगर के स्वतंत्र प्रभात के अखबार के पत्रकार दिनेश चौधरी को जानकारी देते हुए बताया जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में अमृतलाल चौधरी बादल चौधरी एडवोकेट नारायण सिंह कुशराम दयाली अगरिया अमरनाथ सैनी दशरथ चौधरी हीरामणि सिंह संगठन मंत्री इस्माइल अहमद अंसारी कार्यक्रम के अध्यक्ष गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवेश चौधरी कार्यक्रम सचिव संजय चौधरी गोविंद चौधरी आकाश चौधरी विनीत चौधरी मुकेश चौधरी बिना चौधरी उमेश कुमार आशा वंशकार कार्यक्रम आयोजन कार्यकर्ता साहिल पियूष साहू अनुज विनय हिमांशु कृष्ण अजय राजा अंकुश संदीप राहुल सहित चौधरी बबलू वंश का एवं कई बहुजन गोदान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्रम को सफल बनाने में फल बनाने में अपना बहुत योगदान दिया।

पीडब्ल्यूडी- सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता और कोई समय सीमा नहीं

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा- छाता और मांट तहसील के अंतर्गत सड़क का निर्माण खराब गुणवत्ता और समय सीमा के साथ नहीं हो रहा है सड़क में खराब गुणवत्ता की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है जिससे लोगों की जान जा रही है लोगों ने क्षेत्रीय सड़कों को लेकर शिकायतें भी किए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार की साख पर बट्टा लगाने की ठान ली है जिससे सरकार की स्वर्णिम योजनाओं पर पलीता लग सके।

पीडब्ल्यूडी ने खराब सड़क बनाई तो क्षेत्रीय विधायक ने सांसद के सामने उठाया मुद्दा

मथुरा- जिले में भ्रमण के दौरान सांसद हेमा मालिनी ने सभी विधायकों के साथ-साथ अधिकारियों की मीटिंग ली मीटिंग के दौरान मांट विधानसभा के विधायक राजेश चौधरी ने बताया चंद दिनों पहले बनी सड़क बाजना से दिल्लू पट्टी और टेंटी गांव से खैर रोड तक अभी से उखड़ने लगी है जिसे झाड़ू से इकट्ठा कर सकते हैं ग्रामीण फतुल चौधरी निवासी मुडलिया अर्जुन पट्टी ने बताया मंदिर से गांव तक चार दिन पहले सड़क बनी है अभी से उखड़ने लगी है हमने ठेकेदार से शिकायत की हमारी नहीं सुनी इसी गांव के अध्यापक अर्जुन सिंह ने बताया सड़क निर्माण के दौरान लाइन टू लाइन नहीं मिलाई गिट्टी पर कम तरकोल मिलाकर डाल दिया गया निर्माण के दौरान सड़क में बहुत ही डबक हैं गांव बड़ी मुडलिया निवासी मिश्रीलाल ने बताया महीन गिट्टी में तरकोल मिलाकर सीधी सड़क पर डालकर रोड रोलर को घुमा दिया है जिससे सड़क में डबक और अभी से उखड़ने लगी हैं

बिना समय सीमा और खराब सड़क से जा रही है लोगों की जान

मथुरा- अकबरपुर से शेरगढ़ तक रोड निर्माण को शासन ने समय सीमा के साथ मंजूरी दी थी। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते रोड को पूरा नहीं कर पाया। अकबरपुर में नाली ना बनी होने के कारण जल भराव बना रहता है सड़क निर्माण के दौरान 100 मीटर ,200 मी, कहीं-कहीं 400 मी टुकड़े छोड़ दिए गए हैं नौगांव ग्राम पंचायत निवासी सुभाष ने बताया सड़क निर्माण में खराब गुणवत्ता का प्रयोग हुआ है और छोड़े गए टुकड़ों पर निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण विगत 4 महीने में सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई है। लेकिन अभी तक सड़क निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं हुआ है इसी गांव के निवासी मानसिंह ने बताया 2 महीने से काम बंद चल रहा है ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है

वर्जन- यह पूरा मामला मेरी संज्ञान में नहीं है दिखवाता हूं, सीपी सिंह अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी आगरा

आखिर कब मिलेगा छुट्टा मवेशियों के आतंक से छुटकारा आए दिन सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं जिम्मेदार कौन?

● आर्य नगर करनैलगंज मार्ग पर आवारा पशुओं का आतंक, बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं, ग्रामीणों में आक्रोश

स्वतंत्र प्रभात

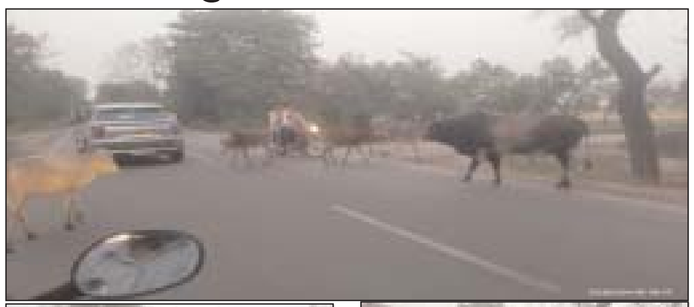

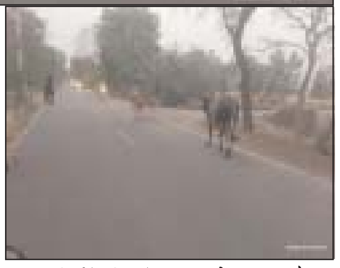

गोंडा – सड़कों पर घूम रहे छुट्टा गोवंशों से हो रही दुर्घटनाएं आए दिन छुट्टा मवेशियों के आतंक से सड़कों पर चलना बन रहीं मुसीबत।विकास खंड रूपईडीह के ग्राम पंचायत हरखापुर क्षेत्र के आर्य नगर करनैलगंज मार्ग पर आवारा पशुओं की भरमार होने से समस्या अब जानलेवा साबित हो रही है। सोमवार देर रात एक तेज़ रफ्तार बाइक की टक्कर एक आवारा पशु से हो गई । जहां पर बाइक सवार बाल बाल बचा।ग्रामीणों का कहना है कि हरखापुर और आस-पास के इलाकों में आवारा पशु सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं। दिन-प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय प्रशासन पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायतों के बावजूद न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है, न ही इन पशुओं को पकड़ने की कोई स्थायी व्यवस्था की जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस समस्या को लेकर आवाज उठाई है, पर समाधान अभी तक नहीं मिला।

प्रशासन के फरमान जारी– प्रशासन ने फरमान जारी किया है कि पशुओ को पकड़ने की विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रमुख सड़कों पर संकेतक बोर्ड और रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाने की बात कही जा रही है।

ग्रामीणों की मांग– ग्रामीणों की मांग है कि आवारा पशुओं के लिए स्थायी गौशाला का निर्माण हो, जिससे पशु सड़कों पर न घूमें और आम जनजीवन सुरक्षित रहे। साथ ही प्रशासन से दुर्घटना होने पर मुआवज़े की भी मांग की है।खंड विकास अधिकारी अभय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि छुट्टा मवेशियों को पकड़वाकर गौशालाओं में किया जा रहा है जो भी गोवंश इधर-उधर घूम रहे हैं उनको भी पकड़वाकर गौशालाओं में किया जाएगा।

रानीपुर टाईगर रिजर्व ने चलाया सफाई अभियान

चित्रकूट ब्यूरो: प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्यूष कुमार कटियार के निर्देशन में जिला गंगा समिति एवं रानीपुर टाइगर रिजर्व के तत्वाधान में बुधवार को मंदाकिनी नदी के सुंदर घाट शंकर बाजार कर्वी में श्रमदान एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कर्वी रेंज स्टाफ ने स्थानीय लोगों के साथ घाट की सीढ़ियों तथा घाट के कोनों में पड़े कूड़ा-कचरे को एकत्र कर परिसर को स्वच्छ किया।

सफाई अभियान के दौरान विकास पथ सेवा संस्थान के डॉ प्रभाकर सिंह ने उपस्थित जन समूह एवं नदी में स्नान करने वाले एवं बच्चों से कहा कि मंदाकिनी नदी हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। इसकी निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है। कहा कि जब हम सभी यह संकल्प लेंगे कि नदी में गंदगी नहीं करेगें, कूड़ा-कचरा नहीं फेकेंगे और दूसरो को भी ऐसा करने से रोकेंगे तो निश्चित ही हमारी मंदाकिनी फिर से स्वच्छ सुंदर और जीवनदायिनी बन सकेगी। कहा कि जन सहभागिता से ही इस पुनीत लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। सफाई अभियान में जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे) गोपाल कृष्ण गुप्ता, प्रकाश श्रीवास्तव, राजू, कर्वी रेंज के स्टाफ बुददा सिंह, माता प्रसाद, अभिषेक, उत्तम अग्रहरि, बच्चा निषाद समाजसेवी आदि ने सहयोग दिया।

सहारा समूह की एम्बी वैली सिटी के पास 707 एकड़ जमीन ईडी ने कुर्क की, 1460 करोड़ रुपये है कीमत

स्वतंत्र प्रभात

पेज नं 1 की शेष खबर

ईडी ने कहा कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं जैसे 'एचआईसीसीएसएल', 'सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' (एससीसीएसएल), 'सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी' (एसयूएमसीएस), 'स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' (एसएमसीएसएल), 'सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एसआईसीसीएल), 'सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एसआई आरईसीएल), 'सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (एसएचआईसीएल) और अन्य कंपनियों के जरिए पोंजी योजना चला रहा था।

ईडी ने कहा, ''समूह ने निवेशकर्ताओं और एजेंट को क्रमशः पैसा जमा करने पर अधिक मुनाफा मिलने और 'कमीशन' का लालच देकर धोखा दिया। समूह ने जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्र धन का उपयोग किया।''ईडी ने कहा, ''समूह ने निवेशकर्ताओं और एजेंट को कोई भी राशि नहीं दी। इसके बजाय जमाकर्ताओं को उनकी परिपक्व हो चुकी राशि को पुनः जमा करने के लिए मजबूर किया तथा जमाराशि को एक योजना से दूसरी योजना तथा अन्य संस्था में स्थानांतरित कर दिया।'

गैर-भुगतान को छिपाने के लिए, समूह ने बही खाता में हेराफेरी की, ताकि एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाया जा सके, तथा पुनर्निवेश को किसी अन्य योजना में नए निवेश के रूप में दर्शाया जा सके। एजेंसी ने कहा कि समूह ने पोंजी योजना को जारी रखने के लिए परिपक्व हो चुकी राशि न चुकाए जाने के बावजूद इसमें नयी जमाएं स्वीकार करना जारी रखा। ईडी ने इस मामले में विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए है।

रैली निकाल नामांकन , स्वच्छता व संविधान के लिये किया गया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। विकास क्षेत्र शोहरतगढ़ के ग्राम पंचायत लेदवा में स्कूल के बच्चों व शिक्षकों ने स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण अभियान,हमारा संविधान-हमारा स्वभिमान कार्यक्रम के तहत बुधवार को रैली निकाल कर गावं की सड़कों, गलियों में भ्रमण किया। विद्यालय से निकल कर बच्चों व शिक्षकों ने लोगों को स्वच्छता अपनाने और स्कूल में बच्चों के नामांकन कार्य में सहयोग देने के लिए नारा लगाया। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती कार्य योजना के तहत बच्चों ने गांव में प्रभात फेरी निकाल हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का नारा लगाया। स्कूल वापस आकर बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की। रैली भ्रमण के दौरान शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बच्चों के नामांकन पर जोर दिया गया। जगह -जगह रुक कर गांव के अभिभावकों से बातचीत करते हुए बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने की अपील की गई, साथ ही साथ गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक अमरेश कुमार, पवन कुमार, राकेश कुमार, मुस्तन शेरुल्लाह, रेनू मद्धेशिया, शशि कुमार यादव, सिद्धार्थ कुमार, राकेश कुमार राज, मनमोहन आदि लोग मौजूद रहे।

अवैध कट बंद कराने को एनएचआई व पीडब्ल्यूडी को निर्देश

● अवैध ई-रिक्शा व अन्य वाहनों पर 965 चालान

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। एसीपी यातायात (मध्य व पश्चिम) आकांक्षा पाण्डेय द्वारा नारामऊ - मंधना हाइवे पर रतन अपार्टमेंट के पास दुर्घटनास्थल व अवैध कट का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा अवैध कट को बंद करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान एनएचआई, पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारी, टीआई पश्चिम (द्वितीय) व थानाध्यक्ष बिठूर भी मौजूद रहे। शासन के आदेश के क्रम में व उच्चधिकारियों के निर्देशन में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष रुप से ई-रिक्शा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, गलत नंबर प्लेट एवं बिना फिटनेस के सम्बन्ध में चेकिंग की गयी और यातायात नियमों का पालन न करने वाले 02 ई-रिक्शा पर एमवी एक्ट के तहत सीज की कार्यवाही एवं 324 ई-रिक्शा का चालान किया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरुक किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। दुर्घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलती है। वाहन चालकों को यह संदेश दिया जाता है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आज यातायात नियमों का पालन न करने वालो पर की गई कार्यवाही की गई। रॉन्ग साइड154, ट्रिपल सवारी टू व्हीलर57, एचएसआरपी 31, अन्य723, कुल 965 चालान किए गए।

सपा कानपुर में पांचो विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथों पर पांच पांच पीडीए कार्यकर्ताओं की टीम बनाएगी

● प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रो की 11 सदस्यीय समिति गठित जो बूथों की टीम का चयन करेगी- हाजी फजल महमूद

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशाअनुसार कानपुर महानगर की गोविंद नगर सीसामऊ आर्य नगर किदवई नगर एवं कैंट विधानसभा क्षेत्रो के 1607 बूथों पर सपा 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम गठित करने को लेकर सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद की अध्यक्षता में सपा कार्यालय प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आरंभ हुई। जिसका संचालन महानगर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिन्टू ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि नगर की पांचो विधानसभा क्षेत्र में 11-11 प्रमुख कार्यकर्ताओं की टीम गठित कर दी गई हैं जो बैठक बुलाकर एक सप्ताह में 1607 बूथों पर पांच सदस्यीय कार्यकर्ताओं की टीम का गठन आरंभ हो जायेगा कमेटी गठन में विधायक पूर्व विधायकों पार्षद पूर्व पार्षद तथा प्रमुख नेतागण जो विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं वह कमेटी में होंगे और पांच सदस्यीय टीम को गठन मे महत्व देकर मतदाता सूची पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने अपने संबोधन में आगे कहा कि शिक्षक अधिवक्ता तथा सभी 15 फ्रंटल संगठनों के लोगों की भी राय लेकर 2027 की रणनीति आरंभ की जाएगी। बैठक मे प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद,प्रदेश सचिव के के शुक्ला,वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिन्टू,महासचिव संजय सिंह बंटी,रजत मिश्रा,नंदलाल जयसवाल,हाजी अयूब आलम,आंनद शुक्ला,महेन्द्र सिह,इशरत इराकी,मुमताज मंसूरी,आकाश यादव,सुलेखा यादव, पूजा यादव,दीप्ती सिह,अनीता वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

भीख मांग रहे बच्चे का होगा संरक्षण

चित्रकूट ब्यूरो: जीआरपी प्रभारी अजय भदौरिया एवं उनकी टीम द्वारा बुधवार को कर्वी रेलवे स्टेशन परिसर में भ्रमण के दौरान भीख मांग कर अपना एवं परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर किशोर को उसकी देखरेख के लिए बाल संरक्षण को सुपुर्द कर दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक विशेष त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को जीआरपी प्रभारी अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान एक नौ वर्षीय बालक सत्यम स्टेशन में भीख मांगते दिखाई पड़ा। टीम द्वारा बच्चे से पूंछताँछ करने पर उसने बताया कि उसके पिता शिवानंद व माता रेनू देवी घरों में जोड़ाई का काम करते हैं। बच्चा दिनभर भीख मांगता है और जो भी पाता है, उससे अपनी मनचाही चीजें खरीदकर खाता है। बच्चा अपने गांव का नाम नहीं बता पाया। जिसके बाद जीआरपी प्रभारी ने बच्चे का मेडिकल कराकर एवं जीडी में एंट्री करने बाद बाल संरक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी के सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्मिक अमित श्रीवास्तव, काजल सिंह, अंजली शुक्ला एवं जीआरपी की टीम मौजूद रही।

कानपुर में किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर लड़के को किया बरामद

● महाराजपुर पुलिस ने चार किडनैपर को गिरफ्तार किया।

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। कमिश्नरेट की महाराजपुर पुलिस ने किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर एक युवक को सकुशल बरामद कर उसके घर वालों को सौंप दिया है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि महाराजपुर थाने पर किडनैपिंग एक मुकदमा लिखा गया था। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव हो गई। और किडनैप हुए युवक को सकुशल बरामद कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है जब कि एक अभियुक्त फरार है। किडनैप हुए युवक शैलेश के पिता इकबाल बहादुर पुत्र रामेश्वर निवासी नगला, सरसौल ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनका पुत्र शैलेश प्रेमपुर से अपने घर नगरा आ रहा था तभी रास्ते में मोटरसाइकिल लगाकर उसे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर एक जगह ले गए। इन लोगों ने एक लाख फिरौती की मांग की। लड़का डर गया था और उसने तुरंत अपने घर फोन किया। तो घर वाले 30 हजार रुपए लेकर बताए स्थान पर पहुंचे लेकिन 30 हजार लेने के बाद भी उन्होंने लड़के को नहीं छोड़ा।

डीसीपी ने बताया इसके बाद उसके पिता ने थाने में खबर दी और मुकदमा दर्ज कराया। थानाध्यक्ष महाराजपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत उनको ट्रेस किया और चार अभियुक्तों को घटना में प्रयोग की गई कार समेत गिरफ्तार किया और शैलेश की सकुशल बरामदगी की। पकड़े गए अभियुक्तों में सूरज ठाकुर पुत्र विजय प्रताप सिंह नि0 थरेपाह थाना नर्वल जिला कानपुर नगर उम्र 26 वर्ष, शिवम पुत्र राज नि0 नर्वल थाना नर्वल जिला कानपुर नगर उम्र 27 वर्ष, विवेक यादव पुत्र बब्बू यादव नि0 बड़ागांव थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर उम्र 25 वर्ष, रवि कुमार पुत्र रामप्यारे नि0 ग्राम रंगोली थाना अलीनगर जिला चन्दौली हाल पता प्रेमपुर रेलवे स्टेशन कालोनी थाना महाराजपुर जिला कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष, हैं। तथा आदिल अहमद पुत्र अनवर अहमद फरार है।